

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

राजस्व अनुभाग-2

दिनांक: १३ जनवरी, 2014

विषय:-जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला में सीमा शुल्क केन्द्र की चौकी की स्थापना हेतु
कुल 0.014 है 0 भूमि कस्टम विभाग, भारत सरकार को सशुल्क आवंटित किये जाने के
संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-र-7719/सात-46/2011-12 दि0-4.2.2013 एवं
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-947/रा०प०-भूमि
ह०/०१२-१३ दि०-२७.२.२०१३ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल,
जनपद पिथौरागढ़ की तहसील एवं ग्राम धारचूला की गैर ज०वि० खतौनी खाता सं0-112,
श्रेणी-९(३)ड बंजर काबिल आबाद के खसरा सं0-५७४० मध्ये ०.००५ है ०, ५७४१ मध्ये ०.००१ है ०,
५७४२ मध्ये ०.००१ है ०, ५७४३ मध्ये ०.००१ है ०, ५७४४ मध्ये ०.००१ है ०, ५७५२ मध्ये ०.००५ है ०,
कुल रकबा ०.०१४ है ० राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-२५८/१६(१)
/७३-राजस्व-१ दिनांक-०९.०५.१९८४ एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-१६९५/९७-१
-१(६०)/९३-२८०-रा०-१ दिनांक-१२.०९.१९९७ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान
प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की मालगुजारी के 100 गुने के
बराबर धनराशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन कस्टम
विभाग, भारत सरकार को पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-१५०/१/८५(२४)-रा-६ दिनांक-०९ अक्टूबर, १९८७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गर्वन्मेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट १८९५ के अधीन पट्टा प्रथमतः ३० वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार ३०-३० वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के १-१/२ गुना से कम नहीं होगा।
- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि 09.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0) / (सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में माओ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृष्ठा सं-२७ / संमिलित / 2014

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. कस्टम विभाग, भारत सरकार।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
20/
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।